दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 12 अंक : 6 ❑ नवम्बर-दिसम्बर, 2020

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

सोशल मीडिया कंपनियों का राजनीति में बढ़ता दखल

कुछ समय पूर्व यह विषय प्रकाश में आया कि कैम्ब्रिज एनालेटिका नाम की एक डाटा कंपनी ने 8.7 करोड़ लोगों के फेसबुक डाटा के आधार पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में काम किया और ट्रंप की विजय में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न यह है कि कैम्ब्रिज एनालेटिका को फेसबुक का डाटा कहां से मिला, तो यह बात स्पष्ट है कि वो फेसबुक कंपनी से ही प्राप्त किया गया। यूं तो फेसबुक कंपनी द्वारा अपने डाटा बेचने के कई साक्ष्य मिलते हैं, और फेसबुक के मालिक मार्क जुकेरबर्ग ने इस संबंध में माफी भी मांगी थी, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

वर्ष 2018 में यह बात सामने आई कि इसी कैम्ब्रिज एनालेटिका कंपनी ने भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए फेसबुक और ट्विटर के डाटा का उपयोग कर 2019 के चुनावों के लिए मतदाताओं के रूझान को बदलने के लिए कार्य करने का प्रस्ताव रखा। इस कंपनी की बेवसाईट पर यह दावा भी किया गया था कि वर्ष 2010 के चुनावों में उसने बिहार चुनावों में विजयी दल के लिए काम किया था। राजनीतिक दलों के लिए चुनावों की दृष्टि से सोशल मीडिया कंपनियों के डाटा का दुरूपयोग एक सामान्य बात मानी जाने लगी है।

लेकिन हालिया अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में इन सोशल मीडिया कंपनियों का दखल और अधिक सामने दिखाई देने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगभग सभी ट्वीटों पर ट्विटर कंपनी की टिप्पणी आ रही थी। इससे स्वभाविक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के सभी बयानों को संदेहास्पद बनाने में इस कंपनी की खासी भूमिका रही। हाल ही में अमरीका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर एकाउंट सस्पेंड कर दिए जाने के कारण ट्विटर कंपनी बड़े विवाद का केन्द्र बन गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास इन प्लेटफार्मों को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की निजी जानकारियां काफी बड़ी मात्रा में होती हैं। ये कंपनियां उनके सामाजिक रिश्तों, जात-बिरादरी, आर्थिक स्थिति, उनकी आवाजाही, उनकी खरीदारियों समेत तमाम प्रकार के डाटा पर अधि कार रखती हैं और इस डाटा का उपयोग वे राजनीतिक दलों के हितसाधन में भी कर सकती हैं। ऐसे में वे प्रजातंत्र को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि यदि सोशल मीडिया का उपयोग ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि ये सोशल मीडिया कंपनियां राजनीति को प्रभावित करने का व्यवसाय करने लगे, तो दुनिया में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही नहीं बल्कि सामाजिक तानाबाना भी खतरे में पड़ जाएगा।

हालांकि ट्विटर कंपनी द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एकांउट को सस्पेंड करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान अमरीका में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए खतरा हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व फ्रांस में एक समूह द्वारा हिंसक गतिविधियों को औचित्यपूर्ण ठहराने वाली मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहातिर मोहम्मद की ट्वीट के बावजूद उनके ट्विटर एकाउंट को सस्पेंड न किया जाना दुनिया में लोगों को काफी अखर रहा है।

अत्यंत ताकतवर हैं ये टेक कंपनियां

गौरतलब है कि अकेले भारत में ही फेसबुक के 33.6 करोड़ से ज्यादा एकाउंट हैं, जबकि इस कंपनी द्वारा चलाई जा रही मैसेजिंग, वायस एवं वीडियो कॉल एप्लीकेशन के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इसी प्रकार फेसबुक इंस्टाग्राम एप की भी मालिक है, जो फोटो और विडियो साझा करने की एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। इससे सीधा-सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या का निजी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा इस कंपनी के पास है। इसी प्रकार भारत में ट्विटर के लगभग 7 करोड़ और दुनिया में 33 करोड़ एकाउंट हैं। फेसबुक, व्हाट्एप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकेडिन आदि सोशल मीडिया ऐप्स हालांकि मुफ्त में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन अपने बड़े डाटाबेस का उपयोग वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करती हैं। इसी प्रकार सर्च इंजन चलाने वाली गूगल कंपनी भी अनेकों बार अपने लॉगरिथम का गलत इस्तेमाल करने की दोषी पाई गई है। आज भारत में विज्ञापन की दृष्टि से गूगल और फेसबुक सर्वाधिक आमदनी कमाने वाली कंपनियां बन चुकी है। इसी प्रकार अन्य कंपनियों के भी अपने-अपने बिजनेस मॉडल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं को काफी संतुष्टि भी प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

लेकिन इनकी बढ़ती लोकप्रियता और इन कंपनियों पर किसी भी प्रकार के अंकुश के अभाव में इन कंपनियों से समाज के तानेबाने को बिगाड़ने और लाभ के लिए कार्य करते हुए प्रजातंत्र को प्रभावित करने की केवल आशंकाएं ही नहीं बल्कि वास्तविक खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन कंपनियों के कार्यकलापों और लॉगरिथम में पारदर्शिता का पूर्णतया अभाव है। और यह बात भी स्पष्ट है कि ये कंपनियां लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं और अपने शेयर होल्डरों के लिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए अग्रसर रहती हैं। इसलिए स्वभाविकतौर पर, चाहे कानून के दायरे में ही रहकर, ये कंपनियां लाभ

कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चूंकि इलैक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया हाल ही में आस्तित्व में आया है, इसलिए विभिन्न देशों के कानून उनको नियंत्रित करने में स्वयं को अक्षम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी कानूनी बाध्यता के अभाव में ये कंपनियां सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने और लोकतंत्र की भावनाओं पर चोट कर सकती हैं।

हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में आया जब चीन की कुछ मोबाईल एप्स अमानवीय एवं असमाजिक कृत्यों में संलग्न थी, तो भी उन्हें प्रतिबंधित करने में सरकार को कानून के अनुसार निर्णय लेने में लंबा समय लगा। हालांकि जनता में चीन के प्रति बढ़ते आक्रोश के चलते बड़ी मात्रा में ऐसी एप्स प्रतिबंधित कर दी गई हैं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि एप्स पर अंकुश लगाना आसान कार्य नहीं होगा। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का खतरा हमेशा रहेगा।

क्या हो सकता है समाधान?

इन कंपनियों के संभावित खतरों के मद्देनजर चीन ने प्रारंभ से ही इन एप्स को अपने देश में प्रतिबंधित किया हुआ है और इन एप्स के मुकाबले में चीनी एप्स को विकसित किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के उनके अपने ही विकल्प हैं। भारत भी ऐसा प्रयास कर सकता है कि चाहे इन सोशल मीडिया एप्स को जारी भी रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ उनके विकल्प भी उपलब्ध हों। बड़ी संख्या में चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने के बाद देश में भारत के ही स्टार्टअप्स के द्वारा अनेकों प्रकार के एप्स विकसित किए भी गए हैं।

इसी प्रकार सरकार सोशल मीडिया एप्स के द्वारा उनके डाटा के दुरूपयोग को रोकने के लिए डाटा संप्रभुता हेतु कानून बनाकर इन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से अपने डाटा को भारत में ही रखने के लिए बाध्य कर सकती है। इन कंपनियों द्वारा डाटा माइनिंग को हतोत्साहित करते हुए भी लोगों के निजी डाटा के दुरूपयोग को कम किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास के इस युग में उपभोक्ता संतुष्टि के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना और सामाजिक तानेबाने को नष्ट करने के प्रयासों को रोकना यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए इन सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून बनाने के दायित्व से सरकारें विमुख नहीं रह सकती।

संपादक